

न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :-श्री हरफूलसिंह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :-174/2024

जी.सी.एम.एस नंबर :- 2024/174

अपीलाण्ट :- बनाम

रेस्पोंडेंट :-

1 पाबुराम पुत्र श्री तेजाराम,
जाति जाट, उम्र वर्ष, निवासी
सुराचंद, तहसील चितलवाना,
जिला सांचौर।

1. तहसीलदार (भूमिधारी) चितलवाना,
जिला सांचौर।
2. आदूराम पुत्र मंशा, जाति जाट, निवासी
पनौरिया, तहसील चौहटन जिला बाडमेर।
3. खेताराम पुत्र मंशा, जाति जाट, निवासी
पनौरिया, तहसील चौहटन जिला बाडमेर।



अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम बखिलाफ आदेश
दिनांक 09.11.2020 उपखण्ड अधिकारी चितलवाना, जिला पूर्व
जालोर वर्तमान सांचौर, राजस्व विविध संख्या 29/2014 बअनवान
पाबुराम बनाम तहसीलदार

उपस्थिति :-

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांक:- 24/12/2024

- न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना के आदेश 29/2014 दिनांक 09.11.2020 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।
- यह दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया। रेस्पोंडेंट बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहे है।
- बहस वकील अपीलांट सुनी गई।
- विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
- अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि -

आदेश जैर अपील विधि, तथ्य व रिकॉर्ड के विरुद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

6
24/12/2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अपीलाण्ट द्वारा खसरा नम्बर 325 रकबा 15 बीघा भूमि जो 2.43 हैक्टेयर की भूमि होती है, जिसको पंजीयन बेचाण द्वारा खरीद की गई, तत्पश्चात् अपीलाण्ट का नाम जमाबन्दी में दर्ज हुआ तथा अपीलाण्ट रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर पर अपीलाण्ट 15 बीघा भूमि पर काबिज कर काशत कर रहा है, परन्तु द्वितीय सेटलमेन्ट के बाद कर्मचारी द्वारा अपीलाण्ट की भूमि का रकबा 2.10 हैक्टेयर दर्ज कर दिया गया, जबकि अपीलाण्ट की कृषि भूमि का रकबा 2.43 हैक्टेयर दर्ज होना चाहिये था, उक्त त्रुटि सद्भाविक त्रुटि है. इस कारण से इसको दुरुस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है व उक्त त्रुटि सेटलमेन्ट के बाद नये खसरा संख्या 1097 में की गई है। इस कारण से अधिनस्थ न्यायालय को द्वितीय सेटलमेन्ट के बाद जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटि की गई है, यह दुरुस्त होने योग्य थी, जिसे दुरुस्त नहीं कर कानूनी व तथ्यात्मक भूल की है।



अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह बताया गया कि अपीलाण्ट के खसरा नम्बर 1097 के पूर्व की तरफ खसरा नम्बर 1098 है, इसके खातेदार खेताराम व आदूराम व पिता मंशा है. इनको प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय को यदि निर्णय के लिए उक्त व्यक्ति आवश्यक पक्षकार मुकदमा होना मानती तो स्वतः ही उक्त व्यक्तियों को सोमोटो पक्षकार बना सकती थी, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सोमोटो पक्षकार नहीं बनाकर जो आवेदन खारिज किया गया है. यह विधिनुसार नहीं है। अपील में रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 व 3 उक्त व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया है। पक्षकार के कुसंयोजन के आधार पर उक्त आवेदन खारिज करने का कानूनी अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को नहीं था, न ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार बनाने हेतु अपीलाण्ट को निर्देश ही दिये गये, जब निर्देश ही नहीं दिये गये तथा सोमोटो पक्षकार नहीं बनाया गया तो आदेश जैर अपील विधि एवं तथ्य के विरुद्ध है।

अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.07.2015 को हल्का पटवारी द्वारा व आर.आई. द्वारा मौका फर्द तैयार की गई तथा इस फर्द के अनुसार अपीलाण्ट के पास जमाबन्दी के अनुसार व नक्शे के अनुसार भूमि कम होना स्पष्ट दर्शित है तथा उक्त कम भूमि 0.33 हैक्टेयर है तथा माफिक नक्शे के भूमि अपीलाण्ट की फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार मार्क ए बी सी डी होनी चाहिये, परन्तु जो भूमि कम है वह भूमि मौका फर्द के नक्शे में मार्क सी.डी. के पश्चिम की तरफ दर्शायी गई है, इस कारण अधिनस्थ न्यायालय को अधिकार अभिलेख जमाबन्दी व नक्शे को दुरुस्त कर अपीलाण्ट का आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिये था, परन्तु आवेदन अस्वीकार कर भारी कानूनी व विधिक भूल की है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु रिबटल के कोई साक्ष्य नहीं थे, इस कारण आवेदन स्वीकार होने योग्य था तथा मौके पर अपीलाण्ट अपनी 15 बीघा यानि की 2.43 हैक्टेयर की भूमि पर काबिज है तथा खसरा नम्बर 1098 के खातेदार भी अपनी

24/12/2024
अतिरिक्त संभागीय अ.स.
पाली (राज.)

कृषि भूमि पर काबिज है तथा मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, इस कारण से जो आदेश पारित किया गया है, यह विधिनुसार नहीं है।

आदेशिका में निर्णय दिनांक 09.11.2020 को सुनाया जाना बताया है, परन्तु निर्णय को देखने मात्र से दिनांक 09.11.2020 को निर्णय लिखाया जाकर सुनाया जाना दर्शित नहीं है। निर्णय के प्रथम पेज पर तथा निर्णय के अंतिम पेज पर तारीख अंकित नहीं है, इसलिये इस दिन निर्णय सुनाये जाने की स्थिति भी निर्णय के अनुसार नहीं है, यहां यह बताना आवश्यक है कि कोरोना महामारी से तालाबन्दी थी तथा न्यायालय में अधिवक्ताओं की उपस्थिति नहीं थी तो बहस होने व निर्णय पारित होने की स्थिति होना भी खिलाफ कानून है। इस कारण से पारित आदेश विधि एवं तथ्य की भूल है तथा हल्का पटवारी सुराचंद द्वारा जो मौका फर्द तैयार की गई. इसके अनुसार जब भूमि अपीलान्ट की कम है तो तकनीकी आधार पर अपीलान्ट दुरुस्ती का अधिकार खारिज करने का अधिकार नहीं था व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है यह विधि एवं तथ्य की भूल है।



अपीलान्ट द्वारा रेकर्ड दुरुस्ती हेतु एक आवेदन उपखण्ड अधिकारी चितलवाना के यहां पेश कर निवेदन किया कि पुराने खसरा नम्बर 325 रकबा 15 बीघा जो हैक्टेयर में 2.43 हैक्टेयर होता है, कि भूमि पंजीयन बेचाण से पुनमा पुत्र गंगा, जाति जाट से दिनांक 18.09.1995 को खरीद की गई, तत्पश्चात् इस कृषि भूमि में अपीलान्ट का नाम जमाबन्दी में दर्ज हुआ तथा इसके बाद द्वितीय सेटलमेन्ट होने पर अपीलान्ट की कृषि भूमि के खसरा नम्बर 1097 कायम किये गये तथा जमाबन्दी तथा नक्शा भी सेटलमेन्ट द्वारा कायम किया गया, परन्तु नया खसरा नम्बर 1097 में अपीलान्ट की कृषि भूमि का रकबा जमाबन्दी में 2.10 हेक्टेयर दर्ज कर दिया गया तथा नक्शे में भी बदलाव कर दिया गया, इसलिये दुरुस्ती अधिकार अभिलेख हेतु अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन पेश किया तथा इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2015 को रिपोर्ट मंगवायी गई, इस रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट की कृषि भूमि 0.33 हैक्टेयर कम होना दर्शाया गया है। बाद सुनवाई के अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 1098 के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किये गये प्रार्थी के आवेदन के विरुद्ध अपील पेश कर निवेदन है कि दिनांक 09.11.2020 को राजस्व विविध संख्या 29/2020 उपखण्ड अधिकारी चितलवाना द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, इस आदेश को निरस्त फरमाया जावे तथा अधिकार अभिलेख जमाबन्दी व नक्शा दुरुस्त किया जावे तथा अपील स्वीकार फरमाया जावे।

6. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। एवं पत्रावली का बगोर अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि प्रकरण में हल्का पटवारी सुराचंद की मौका फर्द दिनांक 03.07.2015 के द्वारा एवं राजस्व नक्शे अनुसार मिलान करने पर रकबा 0.33 हैक्टर खसरा नम्बर 1098

24/12/2024
अतिरिक्त सहायक अधिवक्ता
पाली (राज.)



का रकबा बताया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी वकील द्वारा खसरा नम्बर 1098 के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाकर प्रार्थना पत्र आपने निर्णय दिनांक 9.11.2020 के द्वारा खारीज कर दिया। गुणावगुण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानों के अनुसार सुना जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।



7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तलवाना के आदेश दिनांक 09.11.2020 को अपास्त किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तलवाना को प्रकरण इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए विधिवत निर्णय पारित करे एवं अपीलान्ट को भी निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत समस्त प्रभावित पक्षकारों में प्रकरण में पक्षकार बनाने का संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

24.12.2024
अतिरिक्त सभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक *24.12.2024* को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे-इजलास सुनाया गया।

24.12.2024
अतिरिक्त सभागीय आयुक्त
पाली (राज.)